

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 404
दिनांक 21 अगस्त, 2025

जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जाना

†*404. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देशभर में जैव ईंधन उत्पादक इकाइयों को दिए जा रहे सहयोग का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जैव ईंधन आपूर्ति शृंखला में किसानों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ग) क्या सरकार की जैव ईंधन के लिए फसल अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी पहल शुरू किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जाना’ के बारे में दिनांक 21 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 404 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के उपयुक्त विकल्प के रूप में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

सरकार कई उद्देश्यों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। हरित ईंधन के रूप में, एथेनॉल सरकार के पर्यावरणीय संधारणीय प्रयासों का समर्थन करता है। यह कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करता है और विदेशी मुद्रा की बचत करता है तथा घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। ईबीपी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2014-15 से जुलाई 2025 तक किसानों को 1,25,000 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ है, साथ ही 1,44,000 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, लगभग 736 लाख मीट्रिक टन निवल सीओ₂ की कमी हुई है और 244 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है। ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने जून 2022 में अर्थात् ईएसवाई 2021-22 के लक्ष्य से पाँच महीने पहले, पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, ईएसवाई 2022-23 में यह लक्ष्य 12.06% और ईएसवाई 2023-24 में 14.60% है। इसके अलावा, चालू ईएसवाई 2024-25 के लिए, दिनांक 31.07.2025 तक मिश्रण प्रतिशत बढ़कर 19.05% हो गया है। जुलाई, 2025 के दौरान, 19.93% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया गया है।

भिवानी - महेन्द्रगढ़ लोक सभा क्षेत्र सहित पूरे देश में एथेनॉल उत्पादन को समर्थन देने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल के लिए जीएसटी दर को घटाकर 5% करना, वर्ष 2018-22 के दौरान विभिन्न एथेनॉल ब्याज अनुदान योजना (ईआईएसएस) की शुरुआत, सहकारी चीनी मिलों के लिए एक समर्पित अनुदान योजना ताकि मौजूदा गन्ना आधारित आसवनियों को शीरे के साथ-साथ खाद्यान्न से एथेनॉल उत्पादन के लिए मल्टी-फीडस्टॉक संयंत्र में परिवर्तित किया जा सके, ओएमसीज और समर्पित एथेनॉल संयंत्र के बीच दीर्घकालिक उठान समझौते (एलटीओ), एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एथेनॉल का मल्टीमॉडल परिवहन और एथेनॉल के उच्च मिश्रणों को संभालने के लिए अन्य संबद्ध अवसंरचना के साथ एथेनॉल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके।

एथेनॉल उत्पादन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2019 में " प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन - वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" अधिसूचना जारी की है जिसे वर्ष 2024 में संशोधित किया गया, जिसका उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और फसल अवशेषों सहित अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाएं स्थापित करना, किसानों को उनके अन्यथा बेकार कृषि अवशेषों के लिए पारिश्रमिक आय प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी रोजगार के अवसर पैदा करना, बायोमास/कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की चिंताएँ दूर करना, नगरपालिका के ठोस कचरे से मिट्टी और जल प्रदूषण कम करना, स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम में परिकल्पित लक्ष्य पूरा करने में मदद करना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना आदि हैं। पीएम जी-वन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1,969.50 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,800 करोड़ रुपये वाणिज्यिक पैमाने पर उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए और 150 करोड़ रुपये प्रदर्शन-पैमाने पर उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने जैव डीजल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत डीजल में जैव डीजल के मिश्रण/जैव डीजल की प्रत्यक्ष विक्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित करना, ‘परिवहन उद्देश्यों के लिए हाईस्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव डीजल के विक्रय के लिए दिशानिर्देश-2019’ को अधिसूचित करना, मिश्रण कार्यक्रम के लिए जैव डीजल की अधिप्राप्ति के निमित्त जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करना आदि शामिल हैं।
